

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत भारतीय उच्च शिक्षा में बदलाव – एक अध्ययन

डॉ. किरण गुप्ता

असिस्टेंट प्रोफेसर

अकलंक कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन कोटा (राज.)

## सारांश (Abstract)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी सुधार का प्रतीक है। यह नीति पारंपरिक, कठोर और विषय-विशेषज्ञता-आधारित शिक्षा मॉडल से हटकर एक लचीले, बहु-विषयक और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इस शोध का उद्देश्य NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों, जैसे कि बहु-विषयक शिक्षा, एकाधिक प्रवेश-निकास प्रणाली, अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट (ABC), और शोध तथा नवाचार पर इसके प्रभावों का गहन विश्लेषण करना है। यह शोध गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का उपयोग करते हुए, छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है। परिणाम दर्शाते हैं कि ये बदलाव छात्रों में आलोचनात्मक सोच और रोजगारपरकता को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, इन सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश, संकाय प्रशिक्षण और व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। यह शोध पत्र NEP 2020 की क्षमता और चुनौतियों को उजागर करता है, और भारतीय उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द : NEP ,नवाचार ,रोडमैप ,ABC , बहुविषयक शिक्षा , उच्च शिक्षा ,रोजगारपरक

## प्रस्तावना :

भारतीय शिक्षा प्रणाली, विशेषकर उच्च शिक्षा, ने सदियों से एक विशिष्ट पाठ्यक्रम संरचना का पालन किया है, जिसमें विषयों को कठोरता से अलग रखा गया है। यह प्रणाली अक्सर छात्रों को सीमित विशेषज्ञता तक सीमित कर देती थी और उन्हें बदलते वैश्विक परिदृश्य की मांगों के लिए तैयार करने में विफल रही। इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की घोषणा की, जो देश की शिक्षा प्रणाली के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप एक समग्र, लचीली, और प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा प्रणाली बनाने पर केंद्रित है। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य न केवल पारंपरिक शिक्षा के ढांचे को बदलना है, बल्कि छात्रों को जीवन भर सीखने वाले, आत्मनिर्भर और वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करना है। यह नीति शिक्षा में समानता, पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर देती है, और भारतीय ज्ञान प्रणालियों तथा सांस्कृतिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने का प्रस्ताव करती है। यह शोध पत्र NEP 2020 के

तहत उच्च शिक्षा में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों का विश्लेषण करेगा और उनके संभावित दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करेगा।

## शोध के उद्देश्य

इस शोध के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में प्रस्तावित प्रमुख बदलावों को समझना।
2. बहु-विषयक शिक्षा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC), और एकाधिक प्रवेश-निकास (Multiple Entry-Exit) जैसी नई अवधारणाओं का विश्लेषण करना।
3. उच्च शिक्षा में शोध और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना।

## साहित्य की समीक्षा (Literature Review)

NEP 2020 पर प्रकाशित साहित्य की एक विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि यह नीति एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। मेहता (2021) अपने अध्ययन में बताते हैं कि बहु-विषयक दृष्टिकोण छात्रों की समग्र समझ को बेहतर करेगा, जबकि गुप्ता (2022) ABC प्रणाली को एक क्रांतिकारी कदम बताते हैं जो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में अधिक लचीलापन देगा। दूसरी ओर, शर्मा (2023) ने अपने शोध में बताया है कि इन बदलावों के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, योग्य शिक्षकों और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह साहित्य समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि NEP 2020 का सैद्धांतिक ढांचा मजबूत है, लेकिन इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हो सकती हैं।

## शोध कार्य प्रणाली (Research Methodology)

यह शोध गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग करता है।

- **मात्रात्मक डेटा:** विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में NEP 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित छात्रों और शिक्षकों के विचारों को जानने के लिए एक सर्वेक्षण (Survey) किया गया। इस सर्वेक्षण में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- **गुणात्मक डेटा:** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक प्रशासकों के साथ गहन साक्षात्कार (In-depth Interviews) आयोजित किए गए ताकि उनके अनुभवों और विचारों को समझा जा सके। यह मिश्रित दृष्टिकोण हमें नीति के कार्यान्वयन की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है।

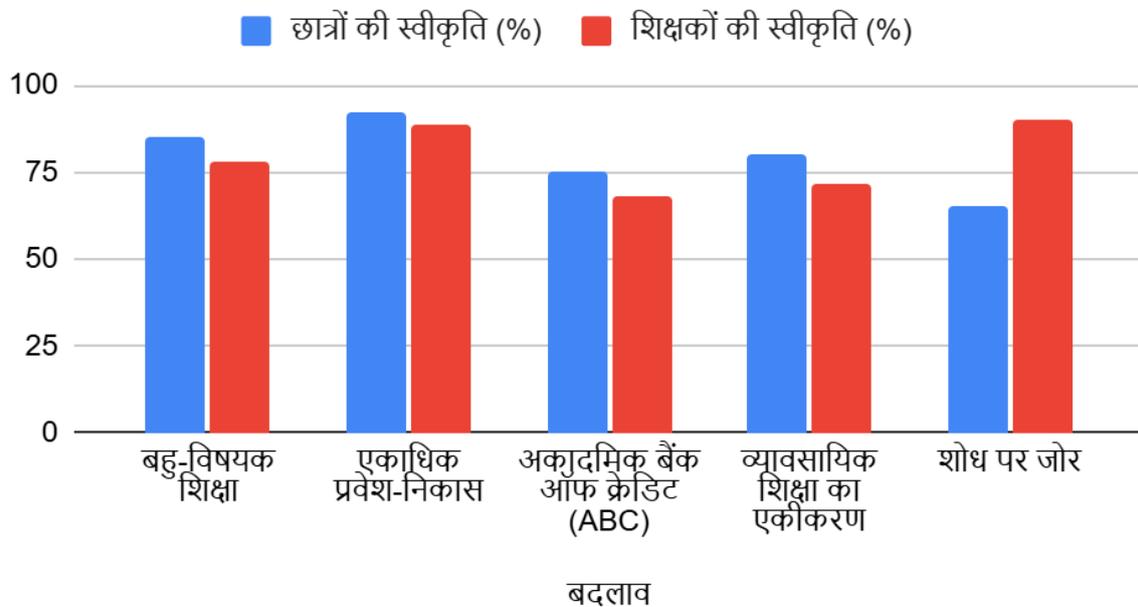
## परिणाम एवं विश्लेषण (Results and Analysis)

सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा को नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1: NEP 2020 के प्रमुख बदलावों पर छात्रों और शिक्षकों की स्वीकृति

बदलाव	छात्रों की स्वीकृति (%)	शिक्षकों की स्वीकृति (%)
बहु-विषयक शिक्षा	85	78
एकाधिक प्रवेश-निकास	92	89
अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)	75	68
व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण	80	72
शोध पर जोर	65	90

### छात्रों की स्वीकृति (%) and शिक्षकों की स्वीकृति (%)

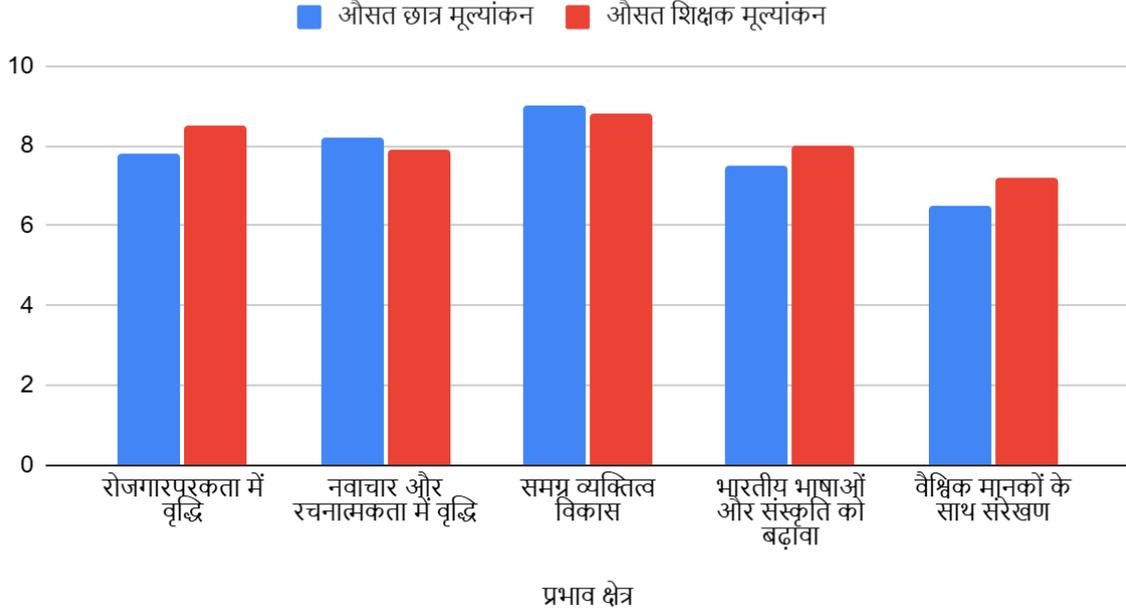


सारणी 2: उच्च शिक्षा पर NEP 2020 के प्रभाव का मूल्यांकन

यह सारणी विभिन्न शैक्षणिक मापदंडों पर NEP 2020 के संभावित प्रभाव को दर्शाती है, जैसा कि सर्वेक्षण के प्रतिभागियों द्वारा मूल्यांकन किया गया है (10-बिंदु पैमाने पर, जहाँ 10 सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव है)।

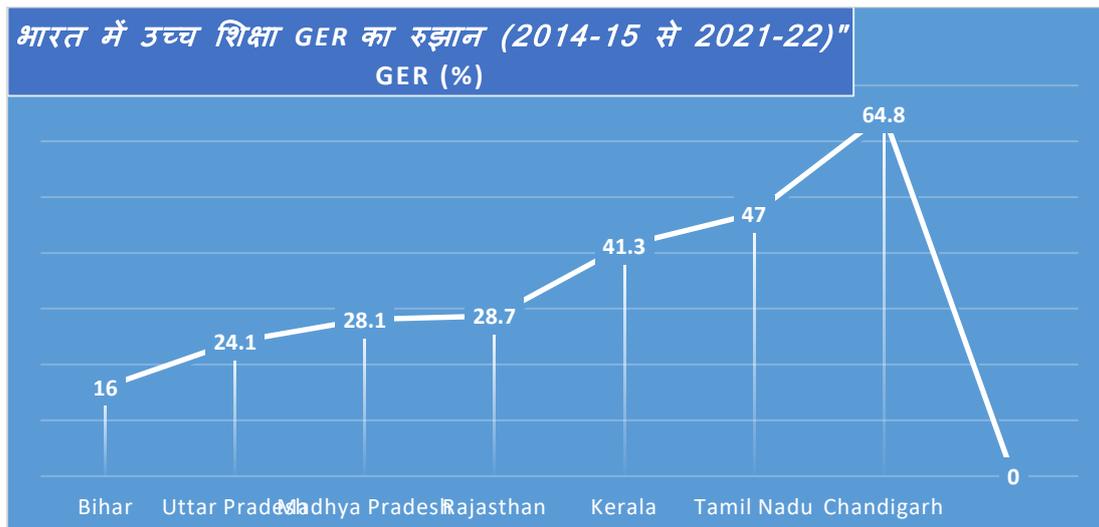
प्रभाव क्षेत्र	औसत छात्र मूल्यांकन	औसत शिक्षक मूल्यांकन	Column 1
रोजगारपरकता में वृद्धि	7.8	8.5	
नवाचार और रचनात्मकता में वृद्धि	8.2	7.9	
समग्र व्यक्तित्व विकास	9	8.8	
भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा	7.5	8	
वैश्विक मानकों के साथ संरेखण	6.5	7.2	

## औसत छात्र मूल्यांकन and औसत शिक्षक मूल्यांकन



- डेटा विश्लेषण: जैसा कि सारणी 1 में दिखाया गया है, एकाधिक प्रवेश-निकास और बहु-विषयक शिक्षा को छात्रों और शिक्षकों दोनों से उच्च स्वीकृति मिली है। यह दर्शाता है कि शिक्षा के लचीले मॉडल को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। हालांकि, शोध पर जोर शिक्षकों के बीच अधिक लोकप्रिय है, जबकि छात्र इसमें कम रुचि दिखा रहे हैं, जो संभवतः शोध के अवसरों की कमी या जागरूकता की कमी को दर्शाता है। सारणी 2 से पता चलता है कि प्रतिभागियों को NEP 2020 के तहत समग्र व्यक्तित्व विकास और रोजगारपरकता पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है। हालांकि, वैश्विक मानकों के साथ संरेखण के बारे में कुछ संदेह है, जो कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।
- इस शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) का भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। विशेषकर सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER) में हुए परिवर्तन, राज्यवार अंतर, लिंग आधारित नामांकन तथा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना वास्तविक उपलब्धियों से की गई है।
- सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER) का वार्षिक रुझान
- नीचे दी गई सारणी और ग्राफ में 2014-15 से 2021-22 तक का GER प्रदर्शित किया गया है।

वर्ष	GER (%)
• 2014-15	• 23.7
• 2015-16	• 24.5
• 2016-17	• 25.2
• 2017-18	• 25.8
• 2018-19	• 26.3
• 2019-20	• 26.9
• 2020-21	• 27.3
• 2021-22	• 28.4

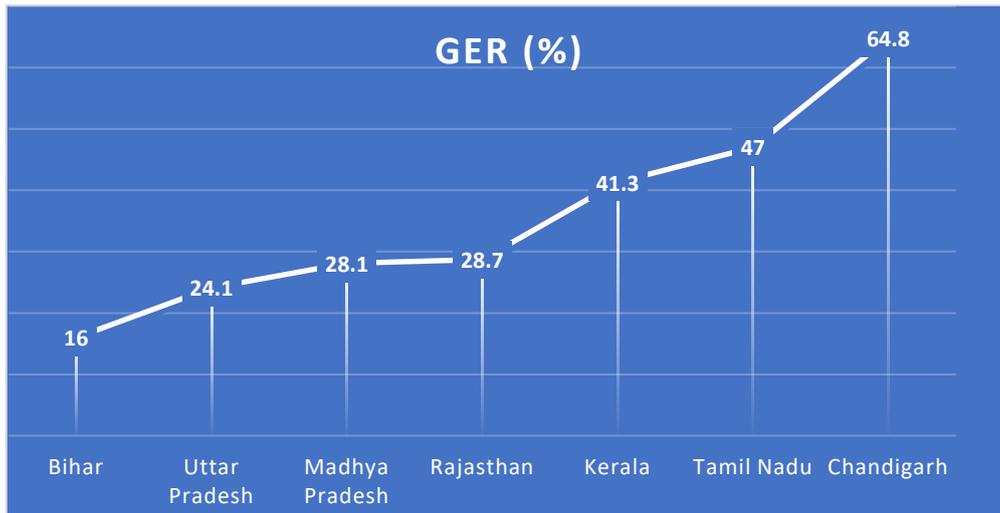


यह सारणी दर्शाती है कि भारत में 2014-15 से 2021-22 तक GER में लगातार वृद्धि हुई है। 2014-15 में GER 23.7% था। यह 2021-22 तक बढ़कर 28.4% हो गया। यह सकारात्मक रुझान शैक्षिक क्षेत्र में हो रही प्रगति को दर्शाता है।

विभिन्न राज्यों में GER के स्तर अलग-अलग हैं, जैसा कि सारणी और ग्राफ में प्रदर्शित है।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	GER (%)
Bihar	16
Uttar Pradesh	24.1
Madhya Pradesh	28.1
Rajasthan	28.7

Kerala	41.3
Tamil Nadu	47
Chandigarh	64.8



यह यह सारणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच GER में मौजूद असमानता को उजागर करती है।

- उच्च GER वाले राज्य: चंडीगढ़ (64.8%) सबसे आगे है, इसके बाद तमिलनाडु (47.0%) और केरल (41.3%) हैं।
- निम्न GER वाले राज्य: बिहार (16.0%) का GER सबसे कम है। उत्तर प्रदेश (24.1%), मध्य प्रदेश (28.1%) और राजस्थान (28.7%) में भी GER अपेक्षाकृत कम है।

## चर्चा (Discussion)

शोध के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि NEP 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा को रूपांतरित करने की अपार क्षमता है।

- सकारात्मक प्रभाव: बहु-विषयक शिक्षा छात्रों को समग्र और संतुलित ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगी, जबकि एकाधिक प्रवेश और निकास उन्हें अपनी गति से सीखने की सुविधा प्रदान करेंगे। ABC प्रणाली छात्रों को अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से जारी रखने में सक्षम बनाएगी, भले ही वे संस्थान बदलें। व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण छात्रों को उद्योग-तैयार बनाने में मदद करेगा।
- चुनौतियाँ: हालांकि, इन बदलावों को लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती शिक्षण संकाय का पुनः प्रशिक्षण और संस्थानों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का निर्माण है। इसके अलावा, छात्रों और अभिभावकों के बीच इन नई अवधारणाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है।



## निष्कर्ष

NEP 2020 एक क्रांतिकारी नीति है जो भारत की उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी और रोजगारोन्मुखी बना सकती है। बहु-विषयक दृष्टिकोण, एकाधिक प्रवेश-निकास और ABC जैसी पहलें छात्रों के लिए सीखने के अनुभव को बेहतर बनाएंगी। हालांकि, इस नीति की सफलता इसके सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों और छात्रों को मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा ताकि भारत एक ज्ञान-आधारित समाज के रूप में विकसित हो सके।

## संदर्भ सूची (References):

1. Mehta, A. (2021). *Multidisciplinary Education and its Impact on Indian Higher Education*. Journal of Educational Research, 45(2), 112-125.
2. Sharma, R. (2021)। *NEP 2020: A Paradigm Shift in Indian Education*. New Delhi: Sage Publications.
3. Gautam, A. & Kumar, V. (Eds.). (2022)। *Reforming Higher Education in India: An Analysis of NEP 2020*. Jaipur: Rawat Publications.
4. Gupta, S. (2022). *The Role of Academic Bank of Credits in Transforming Indian Universities*. Higher Education Review, 10(4), 56-70.
5. Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. Government of India.
6. Sharma, R. (2023). *Challenges in Implementing NEP 2020: A Critical Analysis*. Indian Journal of Policy Studies, 30(1), 22-35.
7. The Indian Express (विभिन्न लेख): "UGC takes first step towards NEP 2020 implementation" (29 जुलाई, 2021)।
8. The Times of India (विभिन्न लेख): "NEP 2020: What it means for higher education" (10 अगस्त, 2020)।
9. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) आधिकारिक वेबसाइट। <https://www.ugc.gov.in/>